छिंदवाड़ा | गुरुवार | 11 जुलाई 2024 | वर्ष 24 | अंक 109 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00 navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत
१९३८ से

5 योगी ने 7720 लेखपालों को दिए नियुक्ति पत्र

6 सुनीता विलियम्स की वापसी कब?

7 मानवीय पूंजी संरचना पर बजट 2024 की तैयारी

8 साउथ अफ्रीका की टीम 84 रन पर ऑल आउट

यूपी सड़क हादसे में 18 की मौत

14 पुरुष और दो महिलाएं हादसे में मारे गए | **19** लोग सड़क हादसे में हुए घायल | **5.15** बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा

- बिहार से दिल्ली जा रही बस टैंकर से टकराई
- सड़क पर बिखरी लाशें देखकर पुलिसकर्मी बेहोश

उन्नाव 10 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर क्षेत्र में बुधवार भोर ट्रक और प्राइवेट बस की भिड़ंत में 18 लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि 19 अन्य घायल हो गये. जिलाधिकारी गौरांठी राठी ने बताया कि आज सुबह करीब सवा पांच बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार निजी बस और दूध के टैंकर में टक्कर हो गयी.

इस हादसे में 18 लोगों की मृत्यु हो गयी है जबकि 19 अन्य गंभीर रुप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है. उन्होने बताया कि प्रथम दृष्टया बस की रफ्तार को हादसे का कारक बताया गया है हालांकि हादसे के कारणों का पता लगाया जायेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है. पुलिस के अनुसार करीब 05.15 बजे थाना बेहटा मुजावर क्षेत्रांतर्गत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे किमी संख्या 247 पर यह हादसा उस समय हुआ जब बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस ने पीछे से दूध से भरे टैंकर को टक्कर मार दी जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गयी. घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया.

मृतकों के परिजनों ने दो-दो लाख की घोषणा

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क दुर्घटना को पीड़ादायक बताते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. श्री मोदी ने कहा कि उन्नाव में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है.

पिपरिया हादसे में 5 की मौत

पेड़ से टकराई कार, शादी समारोह से लौट रहे थे

नर्मदापुरम. पिपरिया में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां एक कार पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. यह सभी शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे. इस दौरान हादसे का शिकार हो गए. यह पूरी घटना पिपरिया थाना क्षेत्र की है. घटना राइस मिल के पास उस वक्त हुई जब टवेरा कार सवार 11 लोग एक शादी समारोह में शामिल होकर सांडिया से लौट रहे थे. इस दौरान राइस मिल के पास उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई. चार लोगों ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया और एक की मौत अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में हुई. अन्य घायलों को एंबुलेंस 108 की मदद से सरकारी अस्पताल पिपरिया ले जाया गया. जहां से 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल नर्मदापुरम रेफर किया गया है.

टक्कर से बस बीच से फट गई

पुलिस क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ अरविंद कुमार ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब माइल स्टोन 247 पर जोगीकोट गांव के पास एक दूध के टैंकर को ओवरटेक करने के प्रयास में निजी बस ने टक्कर मार दी. टक्कर से बस बीच से फट गई है, और पलट गई. साथ ही दूध का टैंकर भी पलट गया. मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करके बस में फंसे लोगों को बाहर निकलवाकर सीएचसी भेजा गया.

अधर में युवाओं का भविष्य

राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना

नई दिल्ली, 10 जुलाई. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के छात्रों के प्लेसमेंट और वार्षिक पैकेज में कथित तौर पर गिरावट को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शिक्षा विरोधी नीयत के कारण मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में है.

उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष अपनी पूरी शक्ति से युवाओं की आवाज निरंतर उठाता रहेगा और इस अन्याय पर सरकार को जवाबदेह बनाकर रहेगा. राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक खबर साझा करते हुए कहा, ''आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव अब देश के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी झेल रहे हैं. आईआईटी में प्लेसमेंट और वार्षिक पैकेज में गिरावट, बेरोज़गारी का चरम झेल रहे युवाओं की स्थिति पर और गहरा आघात कर रहे हैं. 2022 में 19 प्रतिशत छात्रों को कैम्पस प्लेसमेंट नहीं मिल सका और इस वर्ष वही दर बढ़कर दोगुनी, यानी 38 प्रतिशत हो गई.

आज युवा बेरोज़गारी से पूरी तरह टूट चुका

उनका कहना है कि जब देश के सबसे प्रसिद्ध एवं सम्मानित शिक्षा संस्थानों का यह हाल है तो बाकी संस्थानों की क्या दुर्गति होगी? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया, ''आज युवा बेरोज़गारी से पूरी तरह टूट चुका है - पेशेवर शिक्षा पाने में माता-पिता लाखों खर्च कर रहे हैं, विद्यार्थी ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज ले कर पढ़ने पर मजबूर हैं. फिर नौकरी न मिलना, या साधारण आमदनी उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट ही पैदा कर रही है.

एक नजर में

मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है. न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मोहम्मद अब्दुल समद की ओर से तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें उसे (याचिकाकर्ता) अपनी तलाकशुदा पत्नी को 10,000 रुपये का अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था.

केजरीवाल की जमानत मामले में सुनवाई खारिज

नई दिल्ली. उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी, जब ईडी ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था. ईडी के वकील ने कोर्ट में रखी अपनी बातहाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आज मामले की सुनवाई टाल दी.

महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके

मुंबई. महाराष्ट्र के हिंगोली में आज सुबह रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया. ये भूकंप 7.14 पर आया, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी है. राहत की बात ये है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई घटना सामने नहीं आई है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, कुछ महीने पहले भी हिंगोली शहर में 10 मिनट के अंतराल में दो भूकंप आए थे. पहला झटका सुबह लगभग 06.08 बजे महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई.

पश्चिम बंगाल का सीबीआई जांच पर हमला

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसी मामले में जांच की सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई की ओर से जांच जारी रखने को चुनौती देने का पश्चिम बंगाल सरकार का मुकद्दमा सुनवाई करने लायक है. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार की इस प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया कि इस तरह का मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक मूल मुकदमे को सुनवाई योग्य घोषित किया.

मंत्री की पीआरओ ने की खुदकुशी

- मंगलवार सुबह 10.30 बजे लगाई फांसी, रात 11.30 बजे तोड़ा दम
- नहीं मिला सुसाइड नोट,

क्राइम रिपोर्टर

भोपाल, 10 जुलाई. जनसंपर्क संचालनालय की सहायक संचालक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की पीआरओ पूजा थापक ने मंगलवार सुबह अपने घर में फांसी लगा ली. परिजन उन्हें इलाज के लिए एम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां करीब 11 घंटे तक चले इलाज के बाद देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम कराने के बाद लाश परिजन को सौंप दी है. मृतका के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में पति से विवाद की बात सामने आई है. मामला नवविवाहिता से जुड़ा होने के कारण जांच एसीपी द्वारा की जाएगी.

गोविंदपुरा पुलिस के मुताबिक पूजा थापक (33) साकेत नगर में रहती थी. वह जनसंपर्क संचालनालय में सहायक संचालक थी और वर्तमान में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल के पीआरओ का काम देख रही थी. करीब ढाई साल पहले पूजा की शादी निखिल दुबे से हुई थी. निखिल दुबे अरेरा हिल्स स्थित सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक संचालक हैं. दोनों का एक साल का एक बेटा भी है. पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब साढ़े दस बजे दंपति के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद पूजा अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली.

समलैंगिक विवाह मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार करने के अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई नई पीठ के गठन तक बुधवार को स्थगित कर दी. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ को आज (10 जुलाई) न्यायाधीश कक्ष में इस मामले पर सुनवाई करनी थी. इस बीच पांच सदस्यीय इस पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मामले से अपने को अलग कर लिया.

निर्दोष लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं : मोदी

प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर से की मुलाकात

वियना 10 जुलाई वार्ता. रूस की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दूसरे यूरोपीय देश की यात्रा पर ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी और ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने वैश्विक संघर्षों (विशेष रूप से यूक्रेन में चल रहे युद्ध) को सुलझाने में वार्ता और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया.

भारत-ऑस्ट्रिया संयुक्त प्रेस वक्तव्य को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम युद्ध के मैदान में समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे. उन्होंने कहा मुझे ख़ुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला. मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी. 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है.

आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं

आस्ट्रिया की यात्रा पर आये श्री मोदी ने चांसलर नेहैमर के साथ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों पक्षों ने यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित दुनिया में अलग अलग स्थानों पर चल रहे विवादों पर विस्तार से चर्चा की. श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों का मानना है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर भी बल दिया. श्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि यह युद्ध का समय नहीं है. प्रधानमंत्री ने कहा, आज मेरे और चांसलर नेहैमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई.

5 साल सेवा देने वाले कर्मचारी अनफिट

- सीएम की मंत्रियों को दो टूक, ऐसे कर्मियों को हटा दें
- मंत्री स्टॉफ में ऐसे लोगों की पदस्थापना नहीं होगी

कन्हैया लोधी

भोपाल, 10 जुलाई. मप्र में अब मंत्रियों के आसपास मंडराने वाले पुराने अधिकारी- कर्मचारी नजर नहीं आएंगे. अब प्रदेश में किसी भी मंत्री के स्टाफ में ऐसे अधिकारी-कर्मचारी की पदस्थापना नहीं की जा सकेगी, जो कि पहले ही किसी मंत्री के पास अधिकतम 5 वर्ष तक सेवा दे चुके होंगे. यदि किसी अधिकारी- कर्मचारी ने अलग-अलग समयावधि में अलग- अलग मंत्रियों को सेवाएं दी है और उनकी सेवा की अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक रही है तो वे फिर मंत्री स्टॉफ में नियुक्ति के लिए अनफिट होंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को प्रदेश के मंत्रियों को साफ कर दिया है कि वे अब किसी गलतफहमी में नहीं रहें कि वे अपने स्टॉफ में मंत्रियों को लंबे समय तक सेवा देने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का पदस्थ करवा लेंगे. उन्होंने कहा कि यदि मंत्री अघोषित रूप से ऐसे अधिकारी- कर्मचारियों की सेवाएं मंत्री स्टॉफ में ले रहे हैं तो उन्हें रवाना करवा दें, उनके स्थान पर नए अधिकारी- कर्मचारी पदस्थ कराएं, इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है. मंत्री ऐसे प्रस्ताव भेजें और जीएडी से एप्रूव कराएं.अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला बुधवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने उठाया. उनका तर्क था कि अब तक मंत्री स्टॉफ में नियमित नियुक्ति नहीं हो सकी है, इस कारण कामकाज चलाने में दिक्कत आ रही है, उन्होंने अनुभवी स्टॉफ की वकालत की और कहा कि उनके रहने से कामकाज संभालने में आसानी रहती है. बताया जा रहा है कि इस पर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि ये आदेश दिल्ली का है.

40 से अधिक अनफिट अधिकारी दे रहे हैं सेवाएं

प्रदेश के मंत्रियों के स्टॉफ में 40 से अधिक ऐसे अधिकारी- कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के हिसाब से अनफिट हैं. किसी के पास एक तो किसी के पास स्टॉफ में ऐसे दो अधिकारी- कर्मचारी तैनात हैं, अब ऐसे सभी अधिकरी- कर्मचारियों की मंत्री स्टॉफ से रवानगी हो जाएगी, हांलाकि इनमें से ज्यादातर अभी केवल अटैच होकर ही सेवाएं दे रहे थे.

ईवीएम में बंद हुई किस्मत

अमरवाड़ा में 73 फीसदी से अधिक मतदान

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 जुलाई. प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बुधवार को शाम तक 73 फीसदी से अधिक मतदान हो गया था, मतदान समाप्ति के बाद भी कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई थी, इससे मतदान प्रतिशत में अभी और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. मतदान शांतिपूर्ण रहा, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है.

यहां 9 उम्मीदवारों का भाग्य ईव्हीएम में बंद हो गया है, अमरवाड़ा के वोटरों ने किसके सिर जीत का सेहरा बांधा है, इसका खुलासा 13 जुलाई को होगा. यहां भले ही मुकाबला 9 उम्मीदवारों के बीच है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है. ये सीट दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सबब बना हुआ है. भाजपा ने यहां से कमलेश शाह को तो कांग्रेस ने धीरेन शाह को चुनाव मैदान में उतारा है. इधर भाजपा हर हाल में ये सीट कांग्रेस से छीनने पर आमादा है. पिछले विधानसभा चुनाव में वोटिंग 89.09 हुई थी इसके मुकाबले इस साल कम हुई वोटिंग.

कैबिनेट बैठक | राज्य सरकार के लिए विमान खरीदने का दिया अनुमोदन, विमान 45 हजार फीट की ऊंचाई पर भर सकेगा उड़ान

233 करोड़ रुपए में एमपी सरकार खरीदेगी नया विमान

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 जुलाई. मप्र सरकार जल्द ही 233 करोड़ रुपए में नया विमान खरीदने जा रही है. ये विमान कनाडा की बोम्बार्डियर कंपनी से खरीदा जाएगा. चेलेंजर-3500 नाम का ये विमान एक बार फयूल भरवाने पर प्रदेश के बाद नॉनस्टॉप 3300 किलोमीटर की उड़ान भर सकेगा. ये विमान वीआईपी को ध्यान में रखकर खरीदा जा रहा है.

11 सीटर विमान में 9 यात्री और दो क्रू मेंबर सवार हो सकेंगे. कैबिनेट ने बुधवार को राज्य सरकार के लिए विमान खरीदने का अनुमोदन दिया गया है. राज्य सरकार ने विमान खरीदी के लिए टेंडर जारी किया था, राज्य सरकार की जरुरत और अन्य मानकों पर खरा उतरने के बाद इस विमान को खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है. ये विमान अगले वर्ष तक मप्र के विमानन विभाग के बेड़े में शामिल हो जाएगा. राज्य सरकार की इसी जरुरत को ध्यान में रखते हुए ये विमान खरीदा जा रहा है. ये विमान 45 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा, टेकऑफ के लिए जहां इसे महज 1474 मीटर रनवे की जरुरत होगी, वहीं लैंडिंग के लिए महज 702 मीटर रनवे की जरुरत पड़ेगी. वहीं बुधवार को भी कैबिनेट में नर्मदा घाटी विकास विभाग की 9,271 करोड़ 96 लाख रूपये की लागत की 7 परियोजनाओं के निविदा आमंत्रण की अनुमति दे दी गई है. इनमें सोण्डवा, निवाली, सेंधवा आदि सिंचाई परियोजना शामिल है.

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

- विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग के तहत संचालित छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में निवासरत विद्यार्थियों को अजा-जजा कार्य विभाग द्वारा निर्धारित शिष्यवृत्ति दरों के मुताबिक शिष्यवृत्ति मिलेगी.
- बोकरो माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 46 करोड़ रूपये, सैंच्य क्षेत्र 3310 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति.
- इंदौर में सांवेर रोड़ पर निर्माणाधीन केन्द्रीय जेल के शेष रहे निर्माण कार्यों के लिए 217 करोड़ 73 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति.

पेपरलेस होगी विधानसभा

मप्र की विधानसभा अगले एक वर्ष के भीतर पेपरलेस हो जाएगी, इसके लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के क्रियान्वयन को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. इस परियोजना पर 23 करोड़ 87 लाख की लागत आएगी. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि देश की सभी विधान सभाओं को पेपर लेस करने एवं ई-विधान एप्लीकेशन लांच की है।

गुस्ताखी माफ